UNIVERSITY NEWS 22 MAY 2026

DAINIK JAGRAN

अब हर विषय के मूल्यांकन में होगी स्टेप मार्किंग

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार सभी विषयों में 'स्टेप मार्किंग' की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इस निर्णय से विश्वविद्यालय के लाखों परीक्षार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सब्जेक्टिव (विषयपरक/निबंधात्मक) प्रश्नपत्रों के उत्तरों को विभिन्न मुख्य बिंदुओं और चरणों में विभाजित कर जांचा जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी का अंतिम उत्तर किसी कारणवश त्रुटिपूर्ण भी होता है, लेकिन उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और शुरुआती चरण सही हैं, तो उसे प्रत्येक सही चरण के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। इस कदम से किसी भी विद्यार्थी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने द्वितीय परिसर में सभी विषयों के मूल्यांकन प्रभारियों के साथ बैठक में लिया।

कुलपति ने कहा, अक्सर यह देखा जाता रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं की अधिक संख्या होने के कारण मूल्यांकन में एकरूपता की कमी रह जाती है, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र को कई सारे परीक्षक जांचते हैं और सबका नंबर देने का तरीका अलग-अलग होता है जिससे विद्यार्थियों के अंकों में विसंगतियां आने की आशंका बनी रहती थी। मूल्यांकन में पूर्ण एकरूपता बनाए रखने के लिए पहली बार मुख्य परीक्षक और उप-मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक विषय में कितने हेड एक्जामिनर और डिप्टी हेड नियुक्त किए जाएंगे, इसका निर्धारण पूरी तरह से उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा। किस विषय अथवा प्रश्नपत्र में कितने मुख्य परीक्षक नियुक्त होंगे, उनके नामों का चयन संबंधित विभागाध्यक्ष करेंगे।

हर परीक्षक को 50 कापी जांचना अनिवार्य : मूल्यांकन कार्य शुरू होने से पूर्व सभी मुख्य परीक्षक प्रत्येक प्रश्नपत्र सब्जेक्टिव का एक प्रमाणिक साल्यूशन तैयार करेंगे। प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के ''की वर्ड'' निर्धारित किए जाएंगे। कापियों की सुचारू जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य परीक्षक प्रत्येक जांचे गए बंडल में से अनिवार्य रूप से कुल उत्तर पुस्तिकाओं के न्यूनतम पांच प्रतिशत कापियों की स्वयं रैंडम जांच करेंगे।

खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें क्यूआर कोड।

AMAR UJALA

लविवि : पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

पहली बार लागू हुई व्यवस्था, अब अपने चहेतों को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे प्रोफेसर

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने विधि सहित सभी संकायों में गुणात्मक सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। नई व्यवस्था के तहत अब पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कारों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और पक्षपात या मनमाने चयन की आशंकाओं पर रोक लगेगी।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सुरक्षित रखी जाएगी। ऐसे में चयन प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार का विवाद या आरोप लगने पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से जांच संभव होगी। गौरतलब है कि पूर्व में विभिन्न प्रवेश प्रक्रियाओं के दौरान साक्षात्कार में पक्षपात के आरोप सामने आते रहे हैं।

"साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग से चयन प्रक्रिया पर संदेह की स्थिति नहीं बनेगी और मेधावी छात्रों को न्याय मिल सकेगा। विधि सहित सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली और मानवीय मूल्यों को शामिल कर ऐसी पीढ़ी तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पेशेवर रूप से सक्षम होने के साथ नैतिक रूप से भी मजबूत हो।
- प्रो. जेपी सैनी, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय

वहीं, विधि पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली और मूल्यपरक शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत नैतिकता, मानवीय मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़े विशेष विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को केवल कानूनी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक और नैतिक रूप से भी जिम्मेदार बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विभाग के अध्ययन मंडल में शोध छात्रों, उद्योग विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इससे पाठ्यक्रम को रोजगार, उद्योग और शोध की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था विधि सहित सभी विभागों में लागू होगी।

इसके अलावा विधि संकाय के विस्तार के लिए गिरि लाल गुप्ता संस्थान और शंकर दयाल शर्मा संस्थान के भवन विधि विभाग को सौंप दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इन परिसरों में नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

HINDUSTAN

नई व्यवस्था के तहत अब विषयपरक प्रश्नों की जांच चरणबद्ध तरीके से होगी

एलयू की मूल्यांकन व्यवस्था बदली अब स्टेप मार्किंग से दिए जाएंगे अंक

निर्णय

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए स्टेप मार्किंग व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने द्वितीय परिसर में विषयों के मूल्यांकन प्रभारियों की बैठक में घोषणा की।

कुलपति ने कहा कि अब तक एक ही प्रश्नपत्र की कॉपियां कई परीक्षक जांचते थे जिससे अंक देने में एकरूपता की कमी और छात्रों के अंकों में विसंगति की आशंका बनी रहती थी। इसे दूर करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब विषयपरक प्रश्नों की जांच चरणबद्ध तरीके से होगी। यदि अंतिम उत्तर गलत भी हो, लेकिन छात्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही है, तो उसे प्रत्येक सही चरण के अंक दिए जाएंगे। एलयू प्रशासन का दावा है कि इससे लाखों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन हो सकेगा।

मुख्य परीक्षक और डिप्टी हेड नियुक्त होंगे

विश्वविद्यालय में मूल्यांकन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहली बार हेड एग्जामिनर और डिप्टी हेड नियुक्त किए जाएंगे। सभी हेड एग्जामिनर मूल्यांकन शुरू होने से पहले मॉडल सॉल्यूशन और 'की-वर्ड' तैयार करेंगे, जिनके आधार पर कॉपियां जांची जाएंगी। इसके अलावा हर बंडल की कम से कम पांच प्रतिशत कॉपियों की दोबारा रैंडम जांच भी की जाएगी।

परीक्षा में अब हर परीक्षक 50 कॉपियां जांचेगा

विश्वविद्यालय ने कॉपियों के बंडल का आकार 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया है। कॉपियां परीक्षा केंद्रों से सीधे अधिकृत केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन केंद्र पहुंचेंगी। प्रत्येक परीक्षक के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 50 कॉपियां जांचना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन केंद्र सुबह छह बजे से संचालित किए जाएंगे।

कुलपति ने छात्रहित में इसे ऐतिहासिक बताया

एलयू के कुलपति प्रो. जेपी सैनी का कहना है कि यह छात्र हित में ऐतिहासिक कदम है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्रुटिहीन बनेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों और परीक्षकों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ताकि व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन हो सके।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम शुरू

एलयू के योग विभाग एवं फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तहत गुरुवार को एक माह तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। पद्मश्री प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम और निरोग बना हुआ है।

ज्ञान प्रणाली और मूल्य पढ़ेंगे विधि के छात्र

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने विवि में पढ़ाई की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। विश्वविद्यालय ने तय किया है कि लॉ पाठ्यक्रम में अब भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषय शामिल किए जाएंगे। साथ ही मूल्य और मानवीयता जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। विवि ने बोर्ड ऑफ स्टडीज की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। शोधार्थियों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पुरातन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।

I NEXT

लॉ स्टूडेंट्स इंडियन नॉलेज सिस्टम की करेंगे पढ़ाई

लॉ कोर्स मे एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज को भी किया जाएगा शामिल

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (21 May): लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के उद्देश्य से वीसी प्रो. जेपी सैनी ने गुरुवार को कई फैसले लिए, जिससे स्टूडेंट्स न सिर्फ इंडस्ट्री रेडी बनेंगे बल्कि भारतीय परम्परा को भी जानेंगे. पहला फैसला वीसी ने लॉ कोर्सेज के अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम के स्पेशल पेपर एडऑन करने का लिया है. जिसके तहत स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कोर्स में एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज को कंपलसरी तौर पर शामिल किया गया है. जिससे लॉ के स्टूडेंट्स कानून के साथ-साथ एथिक्स की भी पढ़ाई कर सकें.

इंस्टीट्यूट्स को हस्तांतरित किया

लखनऊ यूनिवर्सिटी सेकेंड कैंपस स्थित गिरिलाल गुप्ता और शंकर दयाल शर्मा संस्थान को लॉ फैकल्टी मे हस्तांतरित किया गया और लॉ फैकल्टी के कोर्सेज अब यहीं पर संचालित किए जाएंगे. यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इन संस्थानों मे संचालित कोर्सेज मे स्टूडेंट्स कम होने के चलते इंस्टीट्यूट्स को हस्तांतरित किया गया है.

शामिल होंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट

लखनऊ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक इंटीग्रिटी को रिच करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब हर डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एलुमिनाइज को शामिल किया जाएगा. यह श्री लेवल इनपुट करिकुलम डिजाइनिंग को आज के मार्केट और रिसर्च की जरूरतों के अनुकूल बनाने में हेल्प करेगा. इसके साथ ही पीएचडी एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी के लिए आने वाले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के तहत होने वाले इंटरव्यूज की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे.

स्टूडेंट्स ने किया विरोध

एलयू प्रशासन के मुताबिक गिरिलाल गुप्ता और शंकर दयालशर्मा संस्थान के भवन को लॉ फैकल्टी मे हस्तांतरित करने का निर्णय काफी पहले लिया जा चुका था. जबकि सेकेंड कैंपस स्थित लॉ फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया गुरुवार को फैकल्टी के इंस्पेक्शन के लिए आनी थी, जिसके आधार पर एलयू मे लॉ सीट्स बढ़ेंगी. ऐसे मे काउंसिल को प्रॉपर स्पेस दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से इंजीनियरिंग फैकल्टी और टूरिज्म इंस्टीट्यूट को लॉ फैकल्टी मे तब्दील कर दिया गया. जिसका विरोध करने पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉक्टोरियल बोर्ड की तरफ से डिटेन भी किया गया.

DAINIK JAGRAN

लखनऊ में अपना मकान तो निरस्त होगा आवंटन

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय अपने उन शिक्षक-शिक्षिकाओं का आवास आवंटन निरस्त कर देगा, जिनके पास लखनऊ में अपना मकान है। इसके लिए विश्वविद्यालय की कुलसचिव डा. भावना मिश्रा ने शिक्षकों से 10 रुपये के स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिन के अंदर देने के लिए कहा है।

दरअसल, लवि में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके राजधानी में अपना मकान है। बावजूद इसके वह लवि का आवास आवंटित कराए हुए हैं। अब उन्हें शपथ पत्र देना होगा। जारी पत्र के अनुसार लवि के भवन आवंटन नियमावली में दर्ज प्रविधान के अनुसार शिक्षक-शिक्षिका का अपना या पति/पत्नी के नाम आवास न हो या रेंट कंट्रोल द्वारा आवंटित भवन, लविप्रा, और से आवंटित भवन न हो।

AMAR UJALA

लविवि में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब नई प्रक्रिया से

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में आगामी और वर्तमान परीक्षाओं के मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाने के लिए नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने स्टेप मार्किंग प्रणाली लागू करने और मुख्य परीक्षकों की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है।

स्टेप मार्किंग और मुख्य परीक्षक की व्यवस्था लागू, हर दिन जांचनी होंगी 50 कॉपियां

इस संबंध में आयोजित बैठक के बाद कुलपति ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के अंकों में होने वाली विसंगतियों को दूर करना और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाना है। उन्होंने बताया कि अब सभी विषयों में स्टेप मार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इसके तहत विषयपरक प्रश्नों के उत्तरों का चरणबद्ध मूल्यांकन होगा। यदि किसी छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी हो, तो सही चरणों के लिए उसे अंक दिए जाएंगे, जिससे उसकी मेहनत का उचित मूल्यांकन हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया में पहली बार हेड एग्जामिनर (मुख्य परीक्षक) और डिप्टी हेड (उप-मुख्य परीक्षक) नियुक्त किए जाएंगे। इनकी संख्या उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या के आधार पर तय होगी। परीक्षा नियंत्रक जल्द ही सभी हेड एग्जामिनरों के साथ बैठक करेंगे।

मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख नियम : मूल्यांकन कार्य शुरू होने से पहले हेड एग्जामिनर प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए प्रामाणिक आदर्श उत्तर और उत्तर कुंजी तैयार करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण की-वर्ड निर्धारित किए जाएंगे। हेड एग्जामिनर जांचे गए बंडलों में से न्यूनतम पांच फीसदी कॉपियों की दोबारा गहन जांच भी करेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल का आकार 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इन्हें केंद्रीय एजेंसी से सीधे मूल्यांकन केंद्र भेजा जाएगा। साथ ही प्रत्येक परीक्षक के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 50 कॉपियां जांचना अनिवार्य होगा। (संवाद)

AMAR UJALA

लखनऊ विवि: सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर नियमित परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 23 मई तक अपने परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। पहले यह तिथि 21 मई निर्धारित की गई थी। नियमित छात्रों को परीक्षा फॉर्म के साथ कोई अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करना होगा। उन्हें केवल ऑनलाइन फॉर्म भरकर सेमेस्टर शुल्क रसीद के साथ संबंधित विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष या निदेशक कार्यालय में जमा करना है। वहीं, सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों को ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा। (संवाद)

लविवि ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीपीए, एमए हिंदी, एमए समाजशास्त्र, एमएड, एमएससी का सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 29 मई से शुरू होंगी। परीक्षा कार्यक्रम लविवि की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर भी अपलोड किया गया है। (संवाद)

NBT

LU : मूल्यांकन में पहली बार लागू होगी 'स्टेप मार्किंग'

■ NBT न्यूज, लखनऊ : एलयू परीक्षाओं के मूल्यांकन में सुधार के लिए पहली बार सभी विषयों में 'स्टेप मार्किंग' की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने जा रहा है। इससे लाखों परीक्षार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने द्वितीय परिसर में मूल्यांकन प्रभारियों की बैठक में यह फैसला लिया। प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत सब्जेक्टिव प्रश्नपत्रों के उत्तरों को विभिन्न बिंदुओं और चरणों में विभाजित कर जांचा जाएगा। यदि छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी होता है, तो भी सही प्रक्रिया और शुरुआती चरणों के लिए उसे अंक दिए जाएंगे। मूल्यांकन में एकरूपता के लिए पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या के आधार पर हेड एग्जामिनर (मुख्य परीक्षक) और डिप्टी हेड (उप- मुख्य परीक्षक) नियुक्त किए जाएंगे। इनके नामों का चयन विभागाध्यक्ष करेंगे।

नही पढ़ना होगा दूसरे विभाग का पेपर

■ NBT न्यूज, लखनऊ: एलयू ने एकल विभाग और एक विषय संचालित करने वाले कॉलेजों के उन बच्चों को राहत दी है, जिन्हें परास्नातक पाठ्यक्रम में 'इंटरडिपार्टमेंटल' (अंतरविभागीय) प्रश्नपत्र अनिवार्य किया गया था। अब यहां के छात्र सेकंड सेमेस्टर में उसी विभाग का अन्य पेपर पढ़ सकेंगे।

वीसी प्रो. जेपी सैनी की मंजूरी के बाद इसका आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, अभी तक स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान किसी अन्य विभाग का पेपर पढ़ना पड़ता था। ऐसे में उन कॉलेजों के स्टूडेंट्स को समस्या हो रही थी जहां पर एक ही विषय पढ़ाया जाता था। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है। भविष्य में सभी संबंधित विभागों को कड़ाई से निर्देशित किया गया है कि वे समय रहते छात्रों को अन्य विभागों के विषय चुनने के लिए प्रेरित और निर्देशित करें।

शिक्षक आवास के लिए 3 दिन में देना होगा शपथ पत्र

■ NBT न्यूज, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस स्थित शिक्षक आवासों में रह रहे सभी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय की भवन आवंटन नियमावली के तहत, अब सभी आवंटित शिक्षकों को 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र तीन दिन में देना अनिवार्य कर दिया गया है।

एलयू प्रशासन ने कैंपस स्थित शिक्षक आवासों में रह रहे सभी शिक्षकों के लिए जारी किया आदेश

शपथ-पत्र में शिक्षकों को यह प्रमाणित करना होगा कि लखनऊ शहर में उनका या उनके पति/पत्नी के नाम पर कोई निजी आवास नहीं है। इसके साथ ही, रेंट कंट्रोल, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) या उप्र आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित कोई भी भवन उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी शिक्षक का शहर में अपना मकान पाया जाता है, तो उनका विश्वविद्यालय आवास आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। आदेश के तहत वर्तमान में निवासित सभी शिक्षकों को तीन कार्य दिवसों के भीतर अपना शपथ-पत्र निर्माण विभाग में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

HINDUSTAN

परीक्षा फॉर्म 25 तक भर सकेंगे

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2025-26 सम सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब छात्र-छात्राएं 25 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। यह सुविधा द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को दी गई है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित थी, जिसे विद्यार्थियों के हित में बढ़ाया गया है। जारी निर्देशों के मुताबिक छात्र-छात्राओं को केवल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना होगा।

UNIVERSITY NEWS 22 MAY 2026

HINDUSTAN TIMES

LU announces major reforms for error-free evaluation of copies

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: Lucknow University (LU) on Thursday announced a number of steps aimed at ensuring smooth, fair, and error-free evaluation of answer sheets of the university's upcoming and ongoing examinations.

The reforms include step marking, appointments of head deputy head examiners and re-checking at least 5% of the copies. During a meeting of evaluation in-charges, vice chancellor Prof JP Saini said due to the large number of answer sheets evaluated at the university level, a lack of uniformity in marking has often been observed.

This occurs because the same question paper is checked by multiple examiners. Keeping the larger interests of students in mind, the university administration has introduced reforms in the evaluation system to ensure complete transparency and accuracy in examination results.

Step marking system has been introduced for the first time across all subjects. Under it, subjective/descriptive answers will be evaluated based on different points and procedural steps.

Even if a student's final answer is incorrect, marks will still be awarded for every correct step.

Head and deputy head examiners will also be appointed for the first time.

Their number will depend on the total number of answer sheets and their selection will be made by the respective heads of departments. The Controller of examinations will soon conduct a meeting to ensure smooth implementation of the new system.

Before evaluation commences, all head examiners will be required to prepare authentic model answers and answer keys for each subjective question paper consisting of important keywords and expected points for each question. All examiners will evaluate answer sheets strictly on this basis, the VC said.

He further said every head examiner will mandatorily re-check at least 5% of the evaluated answer sheets from each bundle through random and detailed scrutiny.

Earlier, answer sheet bundles contained 25 copies each which will now be increased to 50 copies per bundle.

Also, each examiner will be required to evaluate a minimum of 50 answer sheets per day.

INCORPORATION OF IKS, VALUE EDU INTO LAW COURSE

LUCKNOW: Lucknow University on Thursday announced incorporation of the Indian Knowledge System (IKS) and value-based education into the law curriculum, along with a syllabus revision involving industry experts and alumni.

Vice chancellor Prof JP Saini said critical subjects such as ethics and human values will be made mandatory for students' all-round development. This is being initiated with the objective to sensitise law students to legal principles as well as ethical and social values. HTC

TIMES OF INDIA

Uniforms mandatory in UP varsities, colleges: Minister

On Guv's Dress Code Directive

Debate over uniforms echoes on campuses in state capital

Mohita Tewari
@timesofindia.com

Anjamaya Singh
@timesofindia.com

Lucknow: Casual clothes will be off the campuses now as UP govt is planning to make uniforms mandatory for students in all state-run universities and colleges. Higher education minister Yogendra Upadhyay announced on Thursday that following the directions of Governor Anandiben Patel

Governor Anandiben Patel

adherence to a dress code would be made mandatory in all universities and colleges across the state.

He said, "As far as possible, a uniform dress code will be implemented in every educational institution to promote a sense of equality and discipline among students."

Upadhyaya said the student community forms a homogeneous group in which no form of discrimination or social hierarchy should be visible. Differences in attire often reflect social and economic inequalities, which can create feelings of inferiority among some students and superiority among others, he said, that the dress code will ensure that all students study in an equal environment.

The minister stressed that govt's objective is not limited to improving academic quality alone, but also to creating a positive, disciplined, and value-based atmosphere in educational institutions.

"Govt is continuously taking reformative measures to provide higher education institutions with a modern and disciplined academic environment. After the implementation of the new system, universities and colleges will develop a more uniform and improved academic culture, which will provide a strong foundation for the goals of Viksit Uttar Pradesh and Viksit Bharat," the minister said.

According to govt officials, the dress code will symbolize discipline and strengthen social harmony and the spirit of equal opportunity. It will help students focus more on education and personality development, they said.

"We already have a uniform in our college, so students from other colleges and universities who used to tease us about it, will now be in uniform too"

Routine will feel repetitive and campus content will lose what makes it interesting." Some students see the practical side.

A uniform can reduce that pressure and level things for everyone," said a law student on Lucknow University second campus.

A student of IT College, Neha Singh, said students are mainly worried as there is no clarity on how much each set will cost or how many will be required. "Buying multiple sets will increase the financial burden on students and their families," she said.

"We already have a uniform in our college, so students from other colleges and universities who used to tease us about it, will now be in uniform too," said Priyanshu Srivastava, a student of National PG College, with a smug smile and note of satisfaction.

She added that making everyone wear the same outfit will make campus environment feel more controlled than creative.

Others say the change will directly impact social media culture.

Mahima Thakur, BTech student at Dr APJ Abdul Kalam Technical University, said, "We plan our outfits based on the kind of reels or photos we shoot on campus, sometimes even coordinating with friends to make the content look better. If everyone is in uniform, that element of creativity will be gone.

AMRIT VICHAR

नैतिकता और मानवीय मूल्य का पाठ पढ़ाएगा लविवि

इंजीनियरिंग संकाय के भवन को विधि संकाय को हस्तांतरित किया गया, विरोध कर रहे छात्रनेता को प्राक्टोरियल टीम ने दौड़ाकर पकड़ा

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन करने की घोषणा की है, जिसमें विधि संकाय के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए अब नैतिकता और मानवीय मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने पढ़ाई की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत अब विधि समेत सभी पाठ्यक्रमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया है कि विधि पाठ्यक्रम में अब भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषय शामिल किए जाएंगे। जिसमें नैतिकता और मानवीय मूल्यों को शामिल किया जाएगा।

कुलपति ने विधि विभाग को निर्देश दिए हैं कि संबद्ध राजकीय और स्ववित्तपोषित कॉलेजों के शिक्षकों के साथ पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। इनमें नए पाठ्यक्रम और पढ़ाई के तरीकों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ स्टडीज की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब इसमें शोधार्थियों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पुरातन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इससे पाठ्यक्रम को रोजगार और वर्तमान जरूरतों के हिसाब से तैयार करने में मदद मिलेगी।

इंजीनियरिंग संकाय का भवन जिसमें अब विधि की पढ़ाई होगी।

रात में ही नाम परिवर्तन की तैयारी करते कर्मचारी।

हम विधि सहित सभी पाठ्यक्रमों में ''इंडियन नॉलेज सिस्टम'' और मानवीय मूल्यों को जोड़कर एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो पेशेवर रूप से सक्षम होने के साथ-साथ नैतिक रूप से भी सुदृढ़ हो। बोर्ड ऑफ स्टडीज में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पुरातन छात्रों और शोधार्थियों को शामिल करने से हमारे पाठ्यक्रम को व्यावहारिक धरातल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पीएचडी साक्षात्कारों की रिकॉर्डिंग करने का निर्णय विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और शुचिता के प्रति हमारी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को दर्शाता है।

–प्रो. जेपी सैनी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय

पीएचडी साक्षात्कार की होगी वीडियो रिकार्डिंग: पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विश्वविद्यालय ने सभी इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष होगी।

दो भवनों अतिरिक्त भवन मिले विधि संकाय को: लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में स्थित गिरि लाल गुप्ता संस्थान और शंकर दयाल शर्मा संस्थान के भवन विधि विभाग को दे दिए गए हैं। यहां विधि संकाय के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। विश्वविद्यालय भविष्य में इन परिसरों में नए रोजगारपरक कोर्स शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है।

DAINIK JAGRAN

विधि संकाय का दायरा बढ़ा, मिले तीन भवन

जासं ● लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय का दायरा बढ़ाने के लिए अब उसे तीन अन्य भवन भी मिल गए हैं। नए आदेश के तहत अभियांत्रिकी संकाय के पाठ्यक्रमों को नए भवन में संचालित किया जाएगा। वहीं, अभियांत्रिकी संकाय के पुराने भवन को विधि संकाय को दे दिया गया है।

प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि गिरि लाल गुप्ता व शंकर दयाल शर्मा संस्थान के भवनों का विधि विभाग को हस्तांतरित किए जाने के लिए विश्वविद्यालय ने पहले ही निर्णय ले लिया था। विधि संकाय के विस्तार के लिए गिरि लाल गुप्ता संस्थान व शंकर दयाल शर्मा संस्थान के दोनों हिस्सों को विधि विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा।

AMRIT VICHAR

लविवि में लागू होगी स्टेप मार्किंग व्यवस्था

अमृत विचार , लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में होने वाली अंक देने की विसंगतियों को दूर करने के लिए स्टेप मार्किंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला न्यू कैंपस में सभी विषयों के मूल्यांकन प्रभारियों के साथ हुई बैठक में कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी द्वारा लिया गया।कुलपति ने कहा कि अब तक अलग-अलग परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन में एकरूपता न होने से छात्रों के अंकों में अंतर आने की शिकायतें मिलती रही हैं। इसे देखते हुए मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित हो सके।नई व्यवस्था के तहत सभी विषयों में स्टेप मार्किंग लागू होगी, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तरों को मुख्य बिंदुओं और चरणों में विभाजित कर जांचा जाएगा। यदि किसी छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया और प्रारंभिक चरण सही हैं, तो उन चरणों के आधार पर अंक दिए जाएंगे।मूल्यांकन शुरू होने से पहले सभी हेड एग्जामिनर प्रत्येक प्रश्नपत्र का प्रामाणिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसमें की-वर्ड निर्धारित किए जाएंगे।हेड एग्जामिनर जांचे गए उत्तर पुस्तिका बंडलों में से कम से कम 5 प्रतिशत कॉपियों की रैंडम दोबारा जांच करेंगे, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।यदि छात्र अंकों से असंतुष्ट होता है तो वह आरटीआई के तहत कॉपी देख सकता है।

TIMES OF INDIA

LU revamps sys of exam evaluation

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lucknow University has announced reforms in its examination evaluation system aimed at improving transparency, fairness and consistency in marking answer sheets.

The initiative introduces step marking, structured evaluation guidelines and stricter monitoring mechanisms for examiners.

Under the new system, subjective answers and essay like questions will be assessed step by step, allowing students to receive marks for each correct point even if the final answer is not fully accurate. The university believes this will ensure that genuine effort is not ignored during evaluation.

Vice-chancellor Prof JP Saini said, "The reform has been designed in the interest of students and to remove inconsistencies in marking, the introduction of step marking and a structured evaluation system is a student-centric decision that will ensure fairness, uniformity and accurate reflection of student performance."

The reform also includes the appointment of head examiners and deputy head examiners in each subject to maintain uniformity.

AMRIT VICHAR

पवनमुक्तासन लाभकारी | अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए लविवि में एक माह के कार्यक्रमों की हुई शुरुआत

पाचन तंत्र की मजबूती के लिए अग्निसार क्रिया

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग एवं फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तहत गुरुवार को एक माह तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने किया। यहां उन्होंने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम और निरोग बना हुआ है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने विषय के प्रति समर्पित रहने, योग को व्यवहारिक जीवन में अपनाने तथा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शोध पत्रों के प्रकाशन पर जोर दिया, ताकि नए ज्ञान का विस्तार हो सके।

योग कार्यक्रम की विवरणिका का विमोचन करते डॉ. अमरजीत यादव, प्रो. आलोक कुमार यादव, प्रो. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. उमेश कुमार। ● अमृत विचार

फैकल्टी के समन्वयक डॉ. अमरजीत यादव ने बताया कि 21 मई से 21 जून तक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अग्निसार क्रिया, पवनमुक्तासन, नौकासन, भुजंगासन, धनुरासन और पश्चिमोत्तानासन लाभकारी हैं। वहीं मोटापा कम करने के लिए सूर्य नमस्कार, सेतुबंध और ताड़ासन उपयोगी बताए गए। घुटनों की समस्या में त्रिकोणासन, ताड़ासन और वृक्षासन और मधुमेह के रोगियों के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन, सिंहासन और मंडूकासन करने की सलाह दी गई। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए गोमुखासन, अर्धचक्रासन और भुजंगासन को प्रभावी बताया गया। संकायाध्यक्ष प्रो. आलोक कुमार यादव ने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। वहीं केजीएमयू के डॉ. राजीव मिश्रा ने कहा कि कैंसर समेत विभिन्न गंभीर बीमारियों और मानसिक रोगों में भी योग सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

NBT

एलयू में पीएचडी इंटरव्यू की होगी विडियो रिकॉर्डिंग

AI Image

■ NBT न्यूज, लखनऊ : एलयू ने पीएचडी में होने वाले दाखिलों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इंटरव्यू की विडियो रिकॉर्डिंग कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र से विधि पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) को शामिल करने का निर्णय लिया है। वीसी प्रो. जेपी सैनी की मंजूरी के बाद कुलसचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

बीओएस में अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और अल्मनाई को मिलेगी जगह

वीसी के नए निर्देशों में लॉ के विद्यार्थियों को कानूनी धाराओं के साथ-साथ नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में 'एथिक्स' और 'ह्यूमन वैल्यूज' के विशेष पेपर जोड़े जाएंगे। इस परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी और स्ववित्तपोषित कॉलेजों के लॉ शिक्षकों के साथ वर्कशॉप आयोजित होंगी। वहीं शैक्षणिक स्तर को व्यावहारिक बनाने के लिए अब विधि सहित सभी विभागों के बोर्ड ऑफ स्टडीज में अनिवार्य रूप से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पुरातन छात्रों और शोधार्थियों को शामिल किया जाएगा।

विधि संकाय का हुआ विस्तार

एलयू ने विधि संकाय में सीटें बढ़ाने के क्रम में नवीन परिसर स्थित विधि संकाय का विस्तार भी कर दिया है। इसके तहत विवि ने 'गिरि लाल गुप्ता संस्थान' और 'शंकर दयाल शर्मा संस्थान' के भवनों को विधि विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इन परिसरों में कम छात्र संख्या वाले पुराने पाठ्यक्रमों को कहीं और भेजकर अब भविष्य में नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने भवन में संचालित इंजीनियरिंग संकाय को नए भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं जबकि इसका भवन भी विधि संकाय को सौंप दिया गया है।

I NEXT

28 मई तक मांगे गए हैं प्रस्ताव

LUCKNOW: लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए निर्देश के बाद भी कई विभागों से अब तक जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) से सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) उच्चीकरण का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है. अब विश्वविद्यालय ने 28 मई तक इसके लिए डेट बढ़ा दी है. कुलसचिव डा. भावना मिश्रा ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है.

सत्र शुरू होने से पहले कराएं अनुमोदन

एलयू ने अशासकी सहायता प्राप्त सहयुक्त महाविद्यालयों से कहा है कि जिनकी प्रबंध समिति एलयू से अनुमोदित नहीं है या कालातीत हो चुका है. वह विधिवत निर्वाचित प्रबंध समिति की मान्यता अनुमोदन का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएं. यह प्रक्रिया सत्र शुरू होने से पहले की जानी है. कुलसचिव डा. भावना मिश्रा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए.

एलयू ने जारी किया एग्जाम प्रोग्राम

एलयू ने कई कोर्सों का एग्जाम प्रोग्राम जारी किया है. बीएड चौथे सेमेस्टर के एग्जाम 11 जून को होंगे. एमए वेस्टर्न हिस्ट्री चौथे सेमेस्टर के एग्जाम 30 मई से 5 जून और एमए कम्पोजिट हिस्ट्री चौथे सेमेस्टर के एग्जाम 30 मई और 1 जून को होंगे. विस्तृत समय सारिणी एलयू की वेबसाइट पर है.